मोबाइल पर खतरा

संपादकीय

दुनिया में सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले मोबाइल फोन पर किसी ताकतवर स्पाइवेयर का खतरा मंडराना बहुत चिंता की बात है। एप्पल कंपनी ने भारत सहित 92 देशों में इस साल के लिए खतरे की सूचना का पहली किस्त जारी की है। इस कंपनी के मोबाइल धारकों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। खतरा कितना बड़ा है, इस संबंध में कंपनी ने आंकड़े जारी नहीं किए हैं, पर सुरक्षित मोबाइल व नेटवर्क का दावा करने वाली यह कंपनी अगर किसी भी स्पाइवेयर को लेकर चिंतित है, तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अव्वल तो सबसे सुरक्षित मोबाइल को निशाना बनाया जा रहा है, तो इसके व्यापक मकसद को समझा जा सकता है। अगर सबसे चर्चित व सुरक्षित मोबाइल निशाने पर है, तो बाकी मोबाइल को कितना सुरक्षित माना जाए? इसे एक ब्रांड पर ही नहीं, बल्कि मोबाइल सेवा पर हमले के रूप में देखा जा सकता है और देखा जाना चाहिए। इससे मोबाइल सेवा की विश्वसनीयता के साथ ही गुणवत्ता पर भी असर पड़ेगा।

ऐसा लगता है कि एक श्रेष्ठ मोबाइल सेवा में सेंध लगाने की यह कोशिश साइबर जासूसी की साजिश का ही विस्तार है। स्पाइवेयर के तहत किसी मोबाइल में एक खास बग या तत्व को पहुंचा दिया जाता है, जो किसी एप या एसएमएस के माध्यम से सूचनाओं को लीक करने लगता है। इससे किसी भी मोबाइल धारक के बारे में तमाम जानकारियां जुटाकर उनका दुरुपयोग हो सकता है। यहां यह बात गौर करने की है कि चूंकि यह फोन महंगा है, इसलिए इसका उपयोग आमतौर पर समाज या व्यवस्था के निर्णायक लोग करते हैं। अगर किसी निर्णायक व्यक्ति के फोन में सेंध लग जाए, तो फिर उससे सेंधमार को बहुत लाभ पहुंच सकता है। निजता का उल्लंघन तो होता ही है, आर्थिक नुकसान की भी भरपूर गुंजाइश रहती है। देखने की बात है कि पेगासस की वजह से भी एप्पल के फोन निशाने पर आए थे, तब एप्पल कंपनी ने बहुत ही कड़े रुख का परिचय दिया था और पेगासस कंपनी को भी घेरे में ले लिया था। अपनी सुरक्षा के घेरे को बनाए रखने की एप्पल कंपनी की चेष्टा वास्तव में अपने ग्राहकों की यथोचित चिंता से उपजी है। वैसे, जरूरी नहीं कि सभी एप्पल फोन धारकों को स्पाइवेयर के जरिये निशाना बनाया जाए। साइबर अपराधी अपने फायदे के लिए कुछ लोगों या कुछ फोन को निशाना बना सकते हैं या बना रहे होंगे। भारत में चूंकि चुनावी मौसम है, इसलिए यहां इस खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। गौर करने की बात है कि दुनिया में अभी पचास से ज्यादा देशों में चुनाव हो रहे हैं, अत:-केवल एप्पल ही नहीं, तमाम मोबाइल फोन निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं को अपने उत्पाद व सेवा सुरक्षा के प्रति सजग हो जाना चाहिए। ग्राहकों या उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सबसे ऊपर रहनी चाहिए। वैसे भी भविष्य उन्हीं कंपनियों का है, जो अपने ग्राहकों के लिए सरकारों से भी लड़ जाती हैं। आज एक बड़ी चिंता दुनिया में उन सरकारों को लेकर भी है, जिन्हें जासूसी का चस्का है। जासूसी के अनेक प्रकरण पहले भी सरकारों द्वारा प्रायोजित रहे हैं। ऐसे में, किसी देश के संविधान के दायरे में कंपनियों की निष्ठा अगर अपने ग्राहकों के प्रति रहे, तो लोग खुद को ज्यादा सुरक्षित और सशक्त महसूस करेंगे। तमाम आईटी कंपनियों को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दोनों ही मोर्चों पर साइबर सुरक्षा का तंत्र मिलकर तैयार करना चाहिए, ताकि वायरस, मैलवेयर या स्पाइवेयर पर शिकंजा कसा रहे।

भारत की बेमिसाल विरासत से दुनिया स्तंभित

विश्व विरासत दिवस- 18 अप्रैल, 2024

ललित गर्ग -

मानव सभ्यता के इतिहास और विरासत को एक साथ सम्मान देने के लिए हर साल 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों को प्रोत्साहित करने, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक स्मारकों और स्थलों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। दुनिया भर के लोग त्योहारों, परंपराओं और स्मारकों के माध्यम से अपनी संस्कृति और विरासत का जश्न मनाते हैं। इस दिवस को मनाते हुए यूनेस्को असाधारण मूल्य के सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों की सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विकास के साथ जुड़े एक समृद्ध इतिहास को बढ़ावा देता है। पहला विश्व धरोहर दिवस ट्यूनीशिया में मनाया गया था। विश्व धरोहर दिवस की शुरुआत 1982 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स (आईसीओएमओएस) ने की थी। इसके बाद 1983 में इसे 'यूनेस्को' की मंजूरी मिली। 1983 के बाद से हर साल अलग-अलग थीम के साथ विश्व धरोहर दिवस दुनियाभर में मनाया जाता है। 2024 की आधिकारिक थीम ÷हमारे वैश्विक विरासत की रक्षा करना÷ है। यूनेस्को किसी स्मारक या स्थल को धरोहर घोषित करता है तो उसके बाद उस जगह का नाम विश्व में काफी मशहूर हो जाता है। जिससे वहां विदेशी पर्यटकों का आवागमन भी काफी बढ़ जाता है, जिसका लाभ सीधा देश की अर्थव्यवस्था एवं वहां के पर्यटन व्यवसाय को मिलता है। विश्व धरोहर घोषित होने के बाद उस जगह का खास ध्यान रखा जाता है और उसकी सुरक्षा भी बढ़ा दी जाती है। यदि ये स्मारक ऐसे देश में है, जिसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो यूनेस्को ही स्मारक की देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाता है।

अंतरराष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद और विश्व संरक्षण संघ ये दो संगठन है, जो इस बात का आकलन करते हैं कि स्थल विश्व धरोहर बनने लायक है या नहीं। साल में एक बार इस विषय के लिए समिति की बैठक होती है और फिर उन जगहों का चयन करती है, उसके बाद दोनों संगठन इसकी सिफारिश विश्व धरोहर समिति से करते हैं। फिर ये फैसला लिया जाता है कि उस जगह को विश्व धरोहर बनाना है या नहीं। विश्व विरासत दिवस की इसलिए अपने आप में एक वैश्विक महत्ता है, क्योंकि इसके जरिए दुनिया में सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने में सहूलियत मिल रही है। विश्व की विरासतें मानव को सतत रूप से प्रेरित करती हैं। सिर्फ किसी समाज की विरासत उसी समाज को प्रेरित नहीं करती बल्कि विश्व के दूसरे समाजों को भी विरासत अच्छी तरह से प्रेरित करती है। विरासत दिवस के चलते पर्यावरण और जागरूकता को बढ़ावा मिलता है। विरासतें विभिन्न समुदायों के बीच रिश्तों को आत्मीय और सम्मानजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और मानवीय उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए महत्वपूर्ण आधार होती हैं। यही वजह है कि विश्व विरासत को दुनियाभर के मानव समाज के लिए महत्वपूर्ण माना गया है।

विश्व विरासत दिवस सिर्फ हमारे जीवन में खुशियों के पलों को लाने में ही मदद नहीं करता बल्कि यह देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का माध्यम भी है। यह पर्यटन को प्रोत्साहन देने का सशक्त माध्यम है। भारत की अर्थव्यवस्था पर्यटन-उद्योग के इर्द-गिर्द घूमती रही है। राजस्थान भारत का एक राज्य है जो विश्व विरासत का समृद्ध केन्द्र है, यह पर्यटन के लिए सबसे समृद्ध राज्य माना जाता है। राजस्थान की पुरातात्विक विरासत या सांस्कृतिक धरोहर केवल दार्शनिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थल के लिए नहीं है बल्कि यह राजस्व प्राप्ति का भी स्रोत है। यूं तो भारत के सभी राज्यों में समृद्ध विरासत देखने को मिलती है। पर्यटन क्षेत्रों से कई लोगों की रोजी-रोटी भी जुड़ी है। प्राकृतिक सुंदरता और महान इतिहास से संपन्न राजस्थान में पर्यटन उद्योग समृद्धिशाली है। राजस्थान देशीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों, दोनों के लिए एक सर्वाधिक आकर्षक पर्यटन स्थल है। भारत की सैर करने वाला हर तीसरा विदेशी सैलानी राजस्थान देखने जरूर आता है। जयपुर के महल, उदयपुर की झीलें और जोधपुर, बीकानेर तथा जैसलमेर के भव्य दुर्ग भारतीय और विदेशी सैलानियों के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक हैं। इन प्रसिद्ध विरासत स्थलों को देखने के लिए यहाँ हज़ारों पर्यटक आते हैं। जयपुर का हवामहल, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के धोरे काफी प्रसिद्ध हैं। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग, सवाई माधोपुर का रणथम्भोर दुर्ग एवं चित्तौड़गढ़ दुर्ग काफी प्रसिद्ध है। यहाँ शेखावटी की कई पुरानी हवेलियाँ भी हैं जो वर्तमान में हैरीटेज होटलें बन चुकी हैं।

पर्यटन ने यहाँ आतिथ्य क्षेत्र में भी रोज़गार को बढ़ावा दिया है। यहाँ की मुख्य मिठाई 'घेवर' है। राजस्थान असंख्य पर्यटन अनुभवों, व्यंजनों और मोहक स्थलों का प्रांत है। चाहे भव्य स्मारक हों, प्राचीन मंदिर या मकबरे हों, नदी-झरने, प्राकृतिक मनोरम स्थल हो, इसके चमकीले रंगों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रौद्योगिकी से चलने वाले इसके वर्तमान से अटूट संबंध है। यहां सभी प्रकार के पर्यटकों को चाहे वे साहसिक यात्रा पर हों, सांस्कृतिक यात्रा पर या वह तीर्थयात्रा करने आए हों, सबके लिए खूबसूरत जगहें हैं। यह राजस्थान पल-पल परिवर्तित, नितनूतन, बहुआयामी और इन्द्रजाल की हद तक चमत्कारी यथार्थ से परिपूर्ण समृद्ध विरासत का खजाना है। इस राजस्थान की समग्र विविधताओं, नित नवीनताओं और अंतर्विरोधों से साक्षात्कार करना सचमुच अलौकिक एवं विलक्षण अनुभव है। देश-दुनिया में हमारे पूर्वजों ने विभिन्न शिल्प-कलाओं में जो शानदार कृतियां (स्मारक, ग्रंथ, मंदिर, किले, महल या मकबरे आदि के रूप में) उकेरीं, वो आज हम सभी के सामने महान सांस्कृतिक धरोहरों के रूप में मौजूद हैं। ये हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं, साथ ही आर्थिक लाभ का जरिया भी बनते हैं।भारतीय संस्कृति में हरे-भरे पेड़, पवित्र नदियां, पहाड़, झरनों, पशु-पक्षियों की रक्षा करने का संदेश हमें विरासत में मिला है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से केवल स्मारक एवं स्थल हीं नहीं, प्रभु श्रीराम जैसे महानायकों का जीवन भी दुनिया के लिये प्रेरणास्रोत रहा है। स्वयं भगवान श्रीराम व माता सीता 14 वर्षों तक वन में रहकर प्रकृति को प्रदूषण से बचाने का संदेश दिया। ऋषि-मुनियों के हवन-यज्ञ के जरिए निकलने वाले ऑक्सीजन को अवरोध पहुंचाने वाले दैत्यों का वध करके प्रकृति की रक्षा की। जब श्रीराम ने हमें प्रकृति के साथ जुड़कर रहने का संदेश दिया है तो हम वर्तमान में क्यों प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने में लगे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रकृति की रक्षा करें। गोस्वामी तुलसीदास ने 550 साल पहले रामचरित मानस की रचना करके श्रीराम के चरित्र से दुनिया को श्रेष्ठ पुत्र, श्रेष्ठ पति, श्रेष्ठ राजा, श्रेष्ठ भाई, प्रकृति प्रेम और मर्यादा का पालन करने का संदेश दिया है। रामचरित मानस एक दर्पण है जिसमें व्यक्ति अपने आपको देखकर अपना वर्तमान सुधार सकता है एवं पर्यावरण की विकराल होती समस्या का समाधान पा सकता है।

अयोध्या में भरत का शासनकाल

भरत अयोध्या के राजा नहीं बनना चाहते थे। वे अपने बड़े भाई श्रीराम का आदर भक्ति की सीमा तक करते थे। उनके लिए श्रीराम के स्थान पर स्वयं को राजा बनने की कल्पना करना भी असंभव था। यद्यपि उनकी माता कैकेयी ने महाराज दशरथ द्वारा पूर्व में उन्हें दिए गए वचनों की याद दिलाते हुए दो वरदान माँग लिए थे, पहला, अपने पुत्र अर्थात् भरत को अयोध्या का राज्य और दूसरा, श्रीराम को चौदह वर्षों का वनवास। श्रीराम के साथ सीता और लक्ष्मण भी जंगल चले जाते हैं। इस दुख में दशरथ अपने प्राण त्याग देते हैं। इस घटनाक्रम के समय भरत और शत्रुघ्न अपनी ननिहाल में थे। गुरु जी उन्हें तत्काल वापस बुलाते हैं। अयोध्या पहुँचकर भरत पर जैसे वज्रपात हो गया, श्रीराम के वनवास का कारण स्वयं को जानकर वे अत्यंत दुखी हो जाते हैं। वे पिता के अंतिम संस्कार के पश्चात श्रीराम को वापस लाने चित्रकूट जाते हैं।

रमेश रंजन त्रिपाठी

रामराज्य को दुनिया की श्रेष्ठ शासन प्रणाली माना जाता है। महाराज दशरथ के परलोकगमन के पश्चात और श्रीराम के राजा बनने से पहले चौदह वर्षों तक भरत ने अयोध्या का राजकाज सम्हाला। उन्होंने स्वयं राजगद्दी पर बैठने के बजाय, श्रीराम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया। चरणपादुकाएं उन सिद्धांतों और मर्यादित आचरण का प्रतीक हैं जिसमें श्रीराम दृढ़ता से खड़े रहते हैं। अर्थात् भरत ने राघवेंद्र सरकार से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुरूप सत्ता का संचालन किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 'श्रीरामचरित मानस' में लिखा है कि भरत चरणपादुकाओं से अनुमति लेकर काम करते थे। 'मागि मागि आयसु करत राज काज बहु भाँति'। रामराज्य की श्रेष्ठता के कारण भरत के शासन काल की अधिक चर्चा नहीं होती। जबकि भरत ने भी अत्यंत कुशलतापूर्वक अयोध्या की राज्य व्यवस्था सम्हाली। इसका प्रमाण महर्षि व्यास कृत ब्रह्माण्ड पुराण के उत्तरखंड का हिस्सा अध्यात्म रामायण के युद्ध कांड में मिलता है जिसमें वनवास के उपरांत अयोध्या लौटे श्रीराम से भरत कहते हैं- प्रभो! मुझे धरोहर रूप में सौंपे हुए आपके इस राज्य को मैं फिर आपको ही सौंपता हूँ। हे जगन्नाथ! आपके प्रताप से मैंने अन्न-भंडार, सेना और कोश आदि पहले से दस गुने कर दिए हैं। 'कोष्ठागारं बलं कोशं कृतं दशगुणं मया'।

भरत अयोध्या के राजा नहीं बनना चाहते थे। वे अपने बड़े भाई श्रीराम का आदर भक्ति की सीमा तक करते थे। उनके लिए श्रीराम के स्थान पर स्वयं को राजा बनने की कल्पना करना भी असंभव था। यद्यपि उनकी माता कैकेयी ने महाराज दशरथ द्वारा पूर्व में उन्हें दिए गए वचनों की याद दिलाते हुए दो वरदान माँग लिए थे, पहला, अपने पुत्र अर्थात् भरत को अयोध्या का राज्य और दूसरा, श्रीराम को चौदह वर्षों का वनवास। श्रीराम के साथ सीता और लक्ष्मण भी जंगल चले जाते हैं। इस दुख में दशरथ अपने प्राण त्याग देते हैं। इस घटनाक्रम के समय भरत और शत्रुघ्न अपनी ननिहाल में थे। गुरु जी उन्हें तत्काल वापस बुलाते हैं। अयोध्या पहुँचकर भरत पर जैसे वज्रपात हो गया, श्रीराम के वनवास का कारण स्वयं को जानकर वे अत्यंत दुखी हो जाते हैं। वे पिता के अंतिम संस्कार के पश्चात श्रीराम को वापस लाने चित्रकूट जाते हैं। वे भलीभाँति जानते थे कि श्रीराम वनवास की अवधि पूरी होने से पूर्व अयोध्या नहीं लौटेंगे। भरत फिर भी अपने अग्रज को मनाने जाते हैं और अपने समर्पण, भक्ति और विनय से चौदह सालों बाद अयोध्या आकर राजगद्दी सम्हालने हेतु श्रीराम की स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कैकेयी ने भरत को राजा बनने का वरदान सीमित अवधि के लिए नहीं माँगा था, वनवास के पश्चात श्रीराम अयोध्या लौटते तब भी राजा भरत ही रहते। भरत अपने उद्देश्य में सफल होते हैं कि चौदह वर्षों बाद राघव अयोध्या के नरेश होंगे। वे अयोध्या से इतर, नंदीग्राम में रहते हुए राजकाज करने लगते हैं।

अयोध्या के शासन का संचालन करने के लिए श्रीराम द्वारा दिए गए सूत्र और स्वयं भरत की कार्यप्रणाली का गोस्वामी तुलसीदास जी ने 'श्रीराम चरित मानस' में संक्षिप्त किंतु सारगर्भित वर्णन किया है। श्रीराम, सीता और लक्ष्मण के वनगमन के समय महाराज दशरथ के कहने पर सुमंत्र उन तीनों को रथ में बिठाकर जंगल में ले जाते हैं। श्रृंगवेरपुर से सुमंत्र को वापस लौटाते हुए राघव भरत के लिए संदेश भेजते हैं कि राजा का पद पाने पर नीति न छोड़ देना, मन, वचन और कर्म से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर सेवा करना। हे भाई! पिता, माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपने को अंत तक निभाना। पिता जी को ऐसे रखना कि वे मेरा सोच न करें। यह सीख तब दी गई थी जब महाराज दशरथ जीवित थे।

दशरथ जी के न रहने पर भरत चित्रकूट जाते हैं। वे चौदह वर्षों तक अयोध्या का राज काज सम्हालने के लिए श्रीराम से सीख देने की आर्त भाव से विनती करते हैं। राघव उन्हें समझाते हैं कि तुम्हारी, मेरी, परिवार, घर और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ और महाराज जनक जी को है। गुरुदेव, मुनि विश्वामित्र और मिथिलापति के होते, हमें, तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मेरा, तुम्हारा परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिता जी की आज्ञा का पालन करें। माता-पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा मानने से पैर कभी कुमार्ग पर नहीं पड़ते। ऐसा विचारकर चिंता छोड़ अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश, खजाना, परिवार, कुटुम्ब आदि की जिम्मेदारी तो गुरु जी सम्हाल लेंगे। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की सलाह मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी की रक्षा करते रहना। भरत की व्यग्रता को शांत करके श्रीराम उन्हें अत्यंत सुंदर प्रतीक से राजधर्म का सार समझाते हैं- मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, जो खाने-पीने को तो अकेला है, परंतु विवेकपूर्वक सभी अंगों का पालन-पोषण करता है। श्रीराम की शिक्षा का सार यही है कि राजा को निरंकुश नहीं होना चाहिए, राजकाज में योग्य व्यक्तियों की सलाह लेते हुए सबकी समुचित देखभाल करनी चाहिए।

श्रीराम की चरणपादुकाएं लेकर भरत अयोध्या लौट आते हैं। जनक जी चार दिन अयोध्या में रुके, समस्त इंतजाम किया और मंत्री, गुरु जी और भरत को राज्य सौंपकर मिथिला चले गए। नगरवासी गुरु जी की सीख मानकर श्रीराम के वापस लौटने की प्रतीक्षा में नियम उपवास करते हुए भोग, सुखों को त्यागकर रहने लगे। भरत ने मंत्रियों और विश्वस्त सेवकों को यथोचित दायित्व सौंप दिए। शत्रुघ्न को शिक्षा दी और माताओं की सेवा में नियुक्त कर दिया। विद्वत्समाज से निवेदन किया कि वे कोई भी आज्ञा देने में संकोच न करें। भरत ने परिजनों और नागरिकों को सब प्रकार से संतुष्ट कर सुखपूर्वक बसाया। फिर उन्होंने शत्रुघ्न के साथ जाकर गुरु जी से नियमपूर्वक रहने की आज्ञा प्राप्त की और सुदिन देख चरणपादुकाओं को राजसिंहासन पर विराजित कराया। वे गुरुदेव और कौशल्या माँ को सिर नवाकर पादुकाओं से आज्ञा ले नंदिग्राम में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। भरत सिर पर जटाजूट बना, मुनियों के वल्कल वस्त्र धारणकर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश का आसन बिछाकर रहने लगे। श्रीराम के वन में निवास करने के कारण भरत भी प्रेमपूर्वक भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम आदि में ऋषियों के तुल्य आचरण करने लगे। उन्होंने तन, मन और वचन से समस्त सुख-सुविधाओं, वस्त्राभूषण, भोग-विलास का त्याग कर दिया।

भरत ने अपने आचरण से सिद्ध किया कि वैराग्य धारण कर लेने पर भी राजकाज का सफलतापूर्वक संचालन किया जा सकता है। वे पूरी सतर्कता एवं सजगता से श्रीराम की धरोहर, अयोध्या की देखभाल करने लगे। उन्होंने गुरुदेव, माताओं, परिजनों से लेकर छोटे-बड़े सभी की सुख-सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा। माना जाता है कि श्रीराम और सीता जी की सुरक्षा के लिए वन में चौदह वर्ष लक्ष्मण सोये नहीं, वे रात भर जागते हुए वीरासन में बैठकर पहरा देते थे। भरत भी चौदह सालों तक श्रीराम की अयोध्या की रक्षा के लिए सजगता पूर्वक जागा करते थे। इसका प्रमाण है, हनुमान जी द्वारा राम-रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए द्रोण पर्वत को लेकर जानेवाली अद्भुत घटना। रात के समय पहाड़ को लेकर जा रहे बजरंग बली अयोध्या के ऊपर से गुजरते हैं, तब भरत उन्हें कोई राक्षस समझकर बाण मारकर गिरा देते हैं। ऐसा तभी संभव था जब भरत रात्रि में जागरण कर चौकसी कर रहे होते। जिस देश का राजा अपनी प्रजा के कल्याण के लिए इतना सजग हो, वहाँ की सेना, कर्मचारी और नागरिक स्वयं कितने सदाचारी, कुशल और कर्मठ होंगे, अनुमान लगाया जा सकता है।

देवताओं की राजधानी अमरावती से बढ़कर ऐश्वर्यशाली अयोध्या में ऋषि-मुनियों की भाँति विरागी जीवन बिताते हुए शासन करना तथा चौदह वर्षों में राज्य के वैभव को दस गुना बढ़ा देने की विलक्षण प्रतिभा के कारण तुलसी बाबा ने भरत के लिए सही ही कहा है- 'सब बिधि भरत सराहन जोगू' अर्थात् सभी प्रकार से भरत प्रशंसा के योग्य हैं।

लाल गलियारे में भी चुनावी बिगुल

मोहन चंद्राकर

आजादी बाद से ही देश में कम्युनिस्ट पार्टी या पार्टियों ने एक ऐसा समाज बनाने का सपना देखना शुरू कर दिया था, जो शोषण-विहीन व समता मूलक हो और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वे समय-समय पर अपनी रणनीति बदलते रहे। एक बड़े सशस्त्र आंदोलन के रूप में तेलंगाना (1948-51) पहला प्रयास था, जो निजाम शासन की ज्यादतियों और भूमि सुधारों के लिए लड़ा गया। इसे राज्य ने बड़ी निर्ममता से कुचल दिया। तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 1952 के पहले आम चुनाव में भाग लिया और देश के कई हिस्सों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई।

झारखंड के लातेहार व गढ़वा और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिलों की सीमाओं को छूता बूढ़ा पहाड़ 2024 के आम चुनावों में प्रतीकात्मक ही सही, इतने महत्वपूर्ण बिंब की तरह क्यों उभरा है? पचास से अधिक किलोमीटर विस्तृत और घने जंगलों वाला यह दुर्गम इलाका पिछले तीन दशकों तक कई प्रदेशों में फैले माओवादियों के ट्रेनिंग और कमांड सेंटर के तौर पर काम करता रहा है। सुरक्षा बलों के लिए लगभग अभेद्य इस इलाके में वाम अतिवादियों की ही चलती थी और यहीं से वे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और महाराष्ट्र तक फैले लाल गलियारे में अपनी गतिविधियों का संचालन करते रहे हैं। पिछले कई आम चुनावों को उनके सशस्त्र हस्तक्षेप ने रक्त-रंजित तो किया ही, राज्य के सामने उनके प्रभाव क्षेत्रों में सही सलामत चुनाव करा पाना मात्र भी एक बड़ी चुनौती रही है। यह चुनौती काफी हद तक खत्म हुई 27 जनवरी, 2023 को, जब झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर बूढ़ा पहाड़ की चोटी पर उतरा और उन्होंने इलाके के विकास के लिए सौ करोड़ रुपये की योजनाओं की घोषणा की।

आजादी बाद से ही देश में कम्युनिस्ट पार्टी या पार्टियों ने एक ऐसा समाज बनाने का सपना देखना शुरू कर दिया था, जो शोषण-विहीन व समता मूलक हो और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वे समय-समय पर अपनी रणनीति बदलते रहे। एक बड़े सशस्त्र आंदोलन के रूप में तेलंगाना (1948-51) पहला प्रयास था, जो निजाम शासन की ज्यादतियों और भूमि सुधारों के लिए लड़ा गया। इसे राज्य ने बड़ी निर्ममता से कुचल दिया। तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 1952 के पहले आम चुनाव में भाग लिया और देश के कई हिस्सों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई।

साल 1967 में पश्चिम बंगाल के एक ग्रामीण इलाके नक्सलबाड़ी से कम्युनिस्टों ने भूमि सुधार को लेकर एक दूसरा हथियारबंद आंदोलन शुरू किया, जिसने भारतीय समाज में राजनीति, साहित्य, आर्थिक नीतियों समेत हर अंग को प्रभावित किया। यहां तक कि हमारी भाषा भी इस आंदोलन के चलते बदली। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के तत्कालीन चेयरमैन माओ से प्रभावित होने के कारण इन्हें नक्सलवादी के साथ-साथ माओवादी भी कहा गया। यह आंदोलन एक दशक तक चला और इसे भी राज्य ने कुचल दिया। इसमें सक्रिय कई कम्युनिस्ट गुट चुनावों में भाग लेने लगे, लेकिन इसी से निकले नेतृत्व ने देश के विभिन्न भागों में सशस्त्र विद्रोहों की ऐसी शृंखलाएं खड़ी कर दीं, जिनसे निपटने में राज्य को दशकों लग गए और अब जाकर ऐसा लगने लगा है कि माओवाद के नाम से जाना जाने वाला यह आंदोलन अपनी अंतिम सांसें ले रहा है।

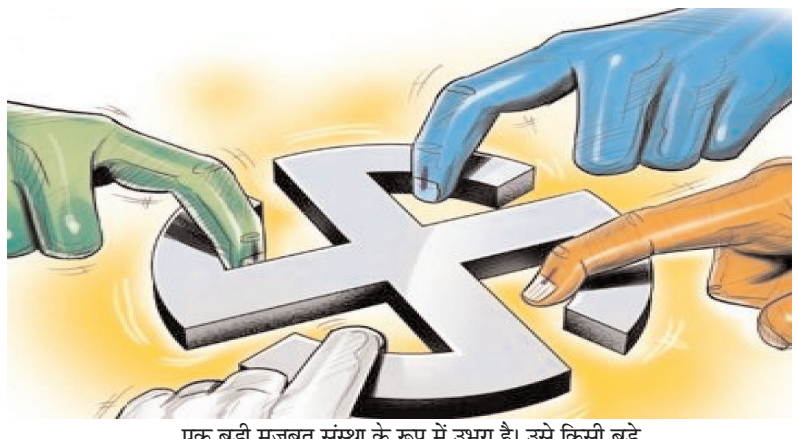

वाम दुस्साहसवाद में विश्वास करने और सशस्त्र संघर्ष से राज्य-सत्ता पर कब्जा करने का सपना देखने वाले इस यथार्थ को नजरअंदाज करते रहे हैं कि पिछली दो शताब्दियों में राज्य एक बड़ी मजबूत संस्था के रूप में उभरा है। उसे किसी बड़े जन-उभार से हिलाया तो जा सकता है, मगर किसी हथियारबंद संगठन द्वारा उस पर कब्जा कर पाना लगभग असंभव है। फिलहाल तो जनता द्वारा सीधे अपने शासकों के चुनाव से बेहतर कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए बार-बार यह नारा देने के बावजूद कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, वाम लड़ाके चुनावों की तरफ लौटते रहे हैं। एक सकारात्मक असर इन संगठनों का यह जरूर दिखा कि सशस्त्र संघर्षों से निकले इनके काडरों ने बिहार जैसे इलाकों के गांवों में दबंगों की बूथ लूटने की घटनाओं पर कुछ हद तक नकेल जरूर लगाई है। दूसरा दिखने वाला असर उन दुर्गम पिछड़े इलाकों में सड़कों, बिजली या संचार के खंभों और शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाओं की पहुंच के रूप में दिखता है, जहां कुछ वर्षों पूर्व तक इनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

चुनावों के दौरान घात लगाकर कुछ पुलिस वालों या चुनाव कर्मियों को मार डालना और मतदान केंद्रों पर लूट-पाट करना आमतौर से प्रचार हासिल करने का सबसे बड़ा माध्यम हुआ करता है। चुनावों की गहमागहमी शुरू होते ही ये अति वामपंथी अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में परचों, पोस्टरों या जनसभाओं के जरिये वोटरों से चुनावों के बहिष्कार की अपील करने लगते हैं। सुरक्षा में सेंध लग जाए, तो उम्मीदवारों या उनके समर्थकों की हत्याएं करने से भी नहीं चूकते। एक मौके पर तो उन्होंने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूरे नेतृत्व का ही सफाया कर डाला था। यह अलग बात है कि भारतीय मतदाता उनकी चेतावनी की उपेक्षा करके बढ़-चढ़कर मतदान करते रहे हैं। इस बार स्थिति कुछ बदली नजर आ रही है। 18वीं लोकसभा के चुनावों की प्रक्रिया शुरू हुए लगभग एक पखवाड़ा हो रहा है और अभी तक माओवादियों के सशस्त्र हस्तक्षेप की कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी है। इससे उम्मीद बंध रही है कि उनके प्रभाव वाले इलाकों में पूरा चुनाव इस बार शांतिपूर्वक निपट जाएगा।

यह परिवर्तन कोई रातोंरात नहीं हुआ। किसी तरह के सशस्त्र नागरिक विद्रोह से निपटने के लिए एक सर्वमान्य प्रविधि तक पहुंचने में भारतीय राज्य को कई दशक लग गए। कभी इसे शांति-व्यवस्था का मुद्दा समझा गया, तो कभी विकास का अभाव कारण माना गया और कभी दोनों। किसी बड़ी घटना से बौखलाकर सरकार कभी बलों की उपस्थिति बढ़ाती, तो कभी वार्ता के नए दौर शुरू करती। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं पहुंच जाने के बाद वहां माओवादियों ने अपने हथियार डाल दिए हों। उलटे यह जरूर हुआ कि उन्होंने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में सड़कें बनने में बाधाएं खड़ी कीं, संचार के खंभे उखाड़ डाले या स्कूलों और अस्पतालों की इमारतें जला दीं। ठेकेदारों, व्यापारियों या सरकारी कर्मचारियों से लेवी के तौर पर वसूले गए धन के नेतृत्व द्वारा दुरुपयोग की शिकायतें आम हो गई हैं। उनकी इन्हीं हरकतों से नागरिक अधिकार संगठनों के वे लोग कमजोर हुए हैं, जो सरकार से बातचीत कर उन्हें मुख्यधारा में लाने की पैरवी करते रहे हैं। हाल के दिनों में केंद्र और राज्य सरकारों का रवैया स्पष्ट रूप से सख्त हुआ है कि बिना हथियार डाले किसी से बात नहीं हो सकेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कई हालिया बयान इस परिवर्तन को स्पष्ट करते हैं। शायद यही कारण है कि दशकों बाद ऐसी संभावना बनी है कि रेड कॉरिडोर के नाम से पहचाने जाने वाले कई हजार वर्ग किलोमीटर और आधा दर्जन प्रदेशों में फैले इलाकों में बिना खून खराबे के चुनाव संपन्न हो रहे हैं।